**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**छावनी बोर्डों को दिए जा रहे सर्विस चार्ज (सेवा प्रभार) की धनराशि**

*152. **श्रीमती सुष्मा स्वराज :**
**डा. जितेन्द्र कुमार जैन :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न नगरों के छावनी बोर्डों को पिछले कुछ वर्षों से "सर्विस चार्ज" (सेवा प्रभार) के रूप में कुछ धनराशि दी जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो छावनी बोर्डों को "सेवा प्रभार" की यह राशि कब से दी जा रही थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि छावनी बोर्डों के लिए यह एक आय का साधन है जिससे वे अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करते हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस संबंध में कतिपय आपत्तियां उठाकर "सेवा प्रभार" की राशि के भुगतान पर पाबंदी लगा दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार स्थानीय विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए पाबंदी लगाए गए क्षेत्रों में घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से कुछ प्रबंध करने का विचार रखती है ?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार)** : (क) से (ग) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विकास कार्य करने के लिए छावनी बोर्डों को वर्ष 1982-83 से सेवा-प्रभार अदा किए जा रहे हैं ।

(घ) और (ङ) बजट व्यवस्था में अत्यधिक कमी के कारण छावनी बोर्डों को देय सेवा-प्रभारों की पूरी राशि का भुगतान करना सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया है । सेवा-प्रभारों की पूरी राशि का भुगतान, धन उपलब्ध होने के बाद ही किया जा सकेगा ।

**लघु विकास केन्द्रों (मिनी ग्रोथ सेन्टर्स) की स्थापना**

*153. **श्री राम जेठमलानी :**
**डा. जितेन्द्र कुमार जैन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के विभिन्न भागों में, विशेषत: पिछड़े क्षेत्रों में, लघु विकास केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रस्ताव को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो जनवरी, 1993 तक देश में कुल कितने लघु विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं और शेष कितने केन्द्रों के कब तक स्थापित किए जाने का लक्ष्य है ?

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्)** : (क) से (घ) 6 अगस्त, 1991 को घोषित लघु, अति लघु और ग्राम्य उद्यमों को बढ़ावा देने और इन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए नीति संबंधी उपायों के अनुसरण में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एक एकीकृत बुनियादी सुविधाओं की विकास (प्रौद्योगिकी सेवाओं सहित) योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

**Production of cement**

*154. SHRIMATI VEENA VERMA :

SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the production of cement during 1992-93, so far;

(b) the comparative figures for 1990-91 and 1991-92; and

(c) whether there is any proposal for setting up or expansion of cement plants in Madhya Pardesh, Gujarat or Maharashtra; if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. *KRISHNA SAHI*) : (a) and (b) Production of cement for the period April, 1992 to January, 1993 was 44.25 million tonnes. Production for the corresponding period was 44.0 million tonnes in 1991-92 and 39.37 million tonnes in 1990-91.

(c) Government has delicensed the cement industry w.e.f. 25th July, 1991. Entrepreneurs are free to establish new undertakings or to effect substantial expansion of the existing undertakings provided the proposals are in accordance with the locational policy of the Government. Under this liberalised policy they are required to file only an Industrial Entrepreneurs' Memorandum (IEM) with the Department of Industrial Development. The details of the Memoranda filed for the period from 1-8-91 to 31-1-93 in respect of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra are as under :—

| S. No. | Name of the State | No. of IEMs filed | Proposed annual installed capacity (lakh tonne) |
|---|---|---|---|
| 1. | Madhya Pradesh | 46 | 392.41 |
| 2. | Gujarat | 15 | 75.92 |
| 3. | Maharashtra | 07 | 19.38 |

**Slow industrial growth in small scale sector**

*155. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the adverse effect on the development of small and cottage industries due to entry of multi-nationals in this field;

(b) what has been the average growth-rate of small scale industries during the last three years up to December, 1992;

(c) what was the total capital investment in the small sector and the number of small scale units that came into existence particularly after the announcement of the new policy of Government indicating to what extent new employment has been generated in the country during the above mentioned period; and

(d) what corrective measures are being taken by government to check the slow industrial growth in small sector.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) No, Sir. Multi-National Companies are not allowed to manufacture items reserved for small scale, unless they undertake to export a minimum 75% of their production.

(b) The annual growth rate of small scale sector during 1990-91, 1991-92* and 1992-93* (upto December, 1992) was 8.5% 2.4% and 6.7% respectively.

*Provisional estimates